अब 54448 करोड़ कर्ज ले सकेगी सरकार

नए वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार 54448 करोड़ रुपए का कर्ज ले सकेगी. जो कि जीएसडीपी का 3 फीसदी होगा.

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 18 फरवरी. यह जानकारी बजट पेश करने के बाद पत्रकार वार्ता के दौरान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने दी. उन्होंने बताया कि ऋण लेना और उसे पूंजीगत मद में खर्च करना सबसे श्रेष्ठ प्रणाली मानी जाती है. दुनिया के सभी देश ऐसा करते हैं. अंतर्राष्ट्रीय मैथेड बना हुआ कि कोई राज्य या देश को कितना कर्ज लेना चाहिए, जिससे कि वह उसे चुका भी सके. ऐसे में जीएसडीपी के 3 फीसदी को ही सबसे आदर्श माना गया है. इसके भीतर लिया गया कर्ज चुकाने में सरकार सक्षम होती है. हमारी कोशिश है कि हम 54 हजार करोड़ रुपए से कम ही कर्ज लें. इस दौरान संचालक बजट राजीव रंजन मीणा ने बजट को लेकर प्रेजेंटेशन भी दिया. उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए जीएसडीपी का पुनरीक्षित अनुमान 16 लाख 70 हजार करोड़ रुपए है, वहीं 16वें वित्त आयोग के गणना के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2026-27 में जीएसडीपी 18 लाख 48 हजार करोड़ रुपए होने का अनुमान है.

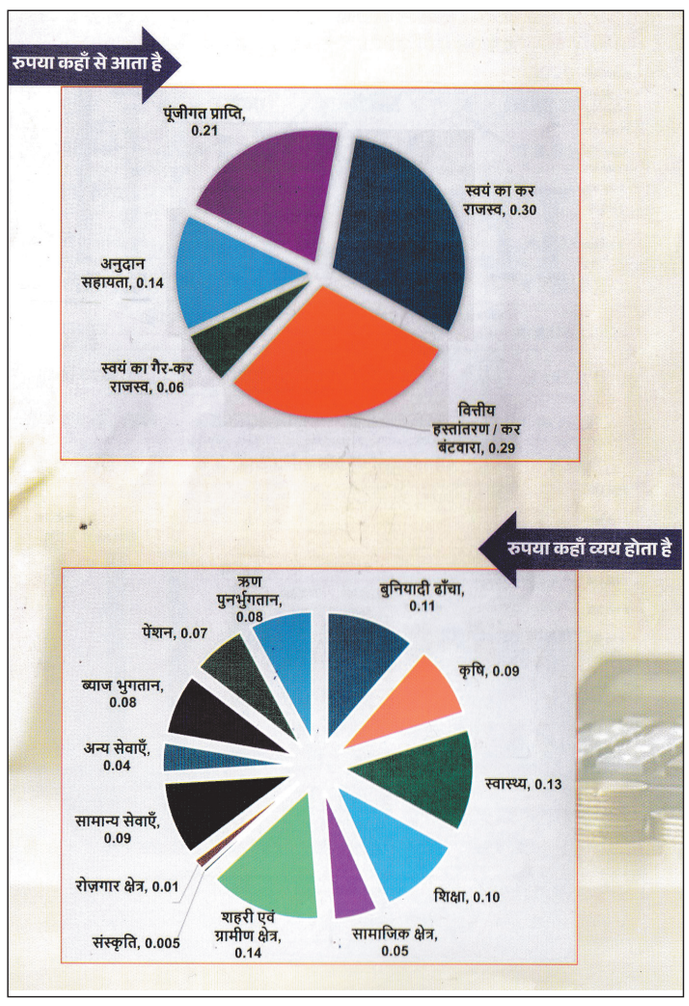

50 हजार सरकारी पदों पर भर्ती होगी

बजट में युवाओं के लिए बड़ी घोषणा

भोपाल. प्रदेश के युवाओं को लुभाने के लिए बजट में एक बार फिर उन्हें सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है. बजट में 50 हजार पदों पर सरकारी भर्तियां होने की घोषणा की गई है. घोषणा के मुताबिक अगले तीन वर्ष के भीतर पुलिस महकमे में 22500 पदों पर भर्ती की जाएगी, इसमें आरक्षक से लेकर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के पद भी शामिल होंगे. इस वर्ष 7500 पदों पर भर्ती की तैयारी की गई है. इसी तरह प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए भी 15 हजार शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया इसी वर्ष शुरू होगी. वहीं दूसरी तरफ जनजातीय क्षेत्रों के स्कूलों के लिए भी 4485 शिक्षकों की भर्ती होगी. उप मुख्यमंत्री ने बजट भाषण के दौरान हर हाथ को काम देने की बड़ी बात भी कही है. **10 लाख नए आवास बनेंगे :** शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के सिर पर छत के लिए सरकार 10 लाख नए आवास बनाएगी. ये आवास अगले 5 वर्ष में बनाने का लक्ष्य तय किया गया है. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर इस वर्ष 6850 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन पर 2 हजार करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी.

यहां से आएगा पैसा (राशि करोड़ में)

राज्य का कर	-	1,17,667
केंद्रीय करों में मप्र का हिस्सा	-	1,12,137
करेत्तर राजस्व	-	24,394
केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान	-	54,505
पूंजीगत मद की राशि	-	80,694
कुल राजस्व प्राप्ति	-	3,89,397

यहां खर्च होगा पैसा...

राजस्व व्यय	-	3,08,659
पूंजीगत व्यय	-	80,266
कुल व्यय	-	3,88,925
राजस्व आधिक्य	-	44.42
कुल बजट राशि	-	4,38,317

समृद्ध, सुखद व सम्पन्न प्रदेश के सपने को पूरा करेगा बजट

मध्यप्रदेश बना रोलिंग बजट प्रस्तुत करने वाला पहला

भोपाल, 18 फरवरी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के "ज्ञान (GYAN)" आधारित विकास के संकल्प के साथ मध्यप्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है. गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के कल्याण के "ज्ञान (GYAN)" के संकल्प में हमारी सरकार ने अब "इंडस्ट्री" और "इंफ्रास्ट्रक्चर" के आई (I) को भी शामिल किया है.

उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश का यह बजट "ज्ञानी (GYANII)" के मार्गदर्शी सिद्धान्त पर तैयार किया गया है, जिसमें गरीब कल्याण, युवा शक्ति के कौशल विकास एवं रोज़गारोन्मुखी प्रशिक्षण, अन्नदाता की आय में वृद्धि, नारी सशक्तिकरण, आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करने का संकल्प है. वर्ष 2026-27 के 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपए के बजट में विकास के लिए पर्याप्त धन राशि रखी गई है. यह बजट "समृद्ध मध्यप्रदेश, सम्पन्न मध्यप्रदेश, सुखद मध्यप्रदेश, सांस्कृतिक मध्यप्रदेश" के सपने को साकार करने वाला है. पिछले वर्ष की तरह इस बार भी प्रदेश की जनता पर किसी नए कर बोझ नहीं डाला गया है.

डॉ यादव ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2024-25 की तुलना में वर्ष 2025-26 में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि के लिए 28 हजार 158 करोड़, आदान व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 64 हजार 995 करोड़, उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए 8 हजार 91 करोड़, सुरक्षा चक्र के लिए 13 हजार 769 करोड़ सहित कृषि कल्याण के लिए कुल 1 लाख 15 हजार 13 करोड़ का बजट प्रस्तावित है, जो किसान कल्याण वर्ष के लिए पर्याप्त है. 2026-27 में पूंजीगत व्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.80 प्रतिशत अनुमानित है.

> मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने रोलिंग बजट को अपनाते हुए वार्षिक बजट को दीर्घकालिक दृष्टि से जोड़ा गया है. रोलिंग बजट प्रस्तुत करने वाला संभवत: मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य है. इस बजट से अगले तीन वर्ष के विकास का खाका खींचा जाएगा और यह बजट विकास के लिए सतत् रूप से पर्याप्त धन राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा. यह बजट च्अमृतकाल 2047ज्ज के लिए विकास का पैमाना सिद्ध होगा. वर्ष 2026-27 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 18 लाख 48 हजार 274 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो वर्ष 2025-26 के अनुमान में 10.69 प्रतिशत अधिक है.

अजा और अजजा के लिए बजट में विशेष प्रावधान

भोपाल, 18 फरवरी. मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में कहा कि बजट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं. श्री देवड़ा ने बजट भाषण में कहा कि कुल बजट में 57 प्रतिशत प्रावधान सामान्य के लिए और अनुसूचित जनजाति तथा जाति के लिए क्रमश. 26 और 17 प्रतिशत का प्रावधान है. बजट में स्थानीय निकायों को राज्य करों के हिस्से की प्रावधानित राशि 4794 करोड़ रुपए है.

झूठे आंकड़ों और खोखले वादों का बजट : सिंघार

भोपाल, 18 फरवरी. विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने राज्य के बजट को झूठे आंकड़ों और खोखले वादों का बजट बताया है. उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश की जनता के साथ छलावा है और जमीनी हकीकत से पूरी तरह कटा हुआ है.

उन्होंने बजट पर प्रतिक्रिया में कहा कि इसमें रिकॉर्ड राजकोषीय घाटा है, इसके बावजूद योजनाओं की लंबी फेहरिस्त पेश की गई है.

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वित्तमंत्री स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि राजकोषीय घाटा 74 हजार करोड़ रुपये से अधिक होगा. जब सरकार के पास संसाधन ही नहीं हैं, तो घोषित योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा. यह बजट सिर्फ घोषणाओं का पुलिंदा है.

उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया गया था, लेकिन बजट में इस पर कोई स्पष्ट नीति, योजना या समयसीमा नहीं है. किसान आज भी लागत और कर्ज के बोझ तले दबा है. जो रूस्क्कके वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं हुए, प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को उम्मीद थी कि भर्ती, नई नौकरियों और रोजगार सृजन पर ठोस प्रावधान होंगे, लेकिन बजट में इस पर कोई ठोस घोषणा नहीं की गई. संविदा भर्ती की बात कही गयी है इससे नौकरी पाने वाले पर हमेशा तलवार लटकी रहेगी.

उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर बजट में कोई प्रावधान नहीं है. यह कर्मचारियों के साथ अन्याय है. नर्मदा किनारे 5 हजार हेक्टेयर में वृक्षारोपण की बात की जा रही है. जब वित्तीय स्थिति कमजोर है तो यह योजना कैसे लागू होगी? पिछली बार भी मां नर्मदा के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ था, इस बार भी वैसी ही आशंका है.

उन्होंन कहा कि बिजली की दरें कम करने पर कोई घोषणा नहीं की गई. आम जनता महंगे बिलों से परेशान है, लेकिन सरकार ने राहत देने की कोई मंशा नहीं दिखाई.

एक तरफ प्रदेश के संसाधन निजी हाथों में सौंपे जा रहे हैं और अडानी जैसे उद्योगपतियों को करोड़ों रुपये दिए जा रहे हैं, दूसरी ओर आम जनता को बिजली बिल में राहत नहीं दी जा रही. सरकार की प्राथमिकताएं साफ हैं—जनता नहीं, उद्योगपति पहले.

विधायकों की मांग थी कि विधायक निधि 2 करोड़ रुपये और बढ़ायी जाए ताकि वे अपने क्षेत्र में विकास कार्य करा सकें. इस मांग की अनदेखी कर सरकार ने न सिर्फ विधायकों बल्कि विधानसभा अध्यक्ष की भावना का भी अपमान किया है.

त्रस्त जनता के लिए निराशाजनक बजट : भाकपा

भोपाल, 18 फरवरी. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने विधानसभा में प्रस्तुत प्रदेश सरकार के बजट को गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त जनता के लिए निराशाजनक निरूपित किया है.

पार्टी के राज्य सचिव शैलेन्द्र शैली ने बजट पर प्रतिक्रिया में कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों पर प्रदेश सरकार ने अपना भारी टैक्स कम नहीं किया. भाजपा द्वारा चुनावों के समय किए गए वादे भी पूरे नहीं किए गए. प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी में सरकारी नौकरी बन्द है. विभिन्न विभागों में लाखों पद रिक्त हैं, लेकिन सरकार ने सिर्फ पुलिस

विभाग में 22 हजार पदों और शिक्षा विभाग में 15 हजार पदों पर नियुक्ति करने का प्रस्ताव किया है. किसानों को उनकी फसल का समर्थन मूल्य देने का कोई प्रावधान नहीं है.

त्वरित टिप्पणी

प्रजा सुखे सुखम राजः सुख और कल्याण आधारित बजट

डॉ ज्योति शर्मा
(अर्थशास्त्रीद्ध)

प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत यह बजट सुख और कल्याण आधारित बजट है. प्रजा का सुख ही राजा का सुख है, इसी भावना पर आधारित बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है. पिछले कुछ वर्षों से मध्य प्रदेश सरकार के बजट का आकार निरंतर बढ़ता जा रहा है. निरंतर बढ़ते 4,38,317 करोड़ के इस बजट में ज्ञान में आई और जोड़कर ज्ञानी किया गया है और यह आई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक है. कैपेक्स यानी पूंजीगत निवेश की मात्रा में वृद्धि है और उसमें सबसे अधिक ध्यान अधोसंरचना के विकास पर है. सड़कों के विस्तार, पुलों के निर्माण, ताप विद्युत, वायु परिवहन संरचना के विस्तार के लिए प्रावधान है. नगरों में मेट्रो ट्रेन के लिए तो गांवों में ग्रामीण सड़क परिवहन के लिए सबसे अधिक प्रावधान रखे गए हैं.

बजट की दूसरी प्रमुख प्राथमिकता ई पर है. जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल, ई समन या वारंट पेपरलेस करने के लिए, कर्मचारियों के लिए ई जी पी एफ जैसे नवीन प्रावधान है.

हरित बजट में वन क्षेत्र आधारित विभिन्न योजनाएं, अभ्यारण विस्तार, वृक्षारोपण कार्यक्रम, चंदन वृक्षों का रोपण, कृषि वानिकी, वन विविधता जैसे अनेक प्रावधान है जो स्वागत योग्य है.

वन पर्यटन के अतिरिक्त मध्य प्रदेश धार्मिक पर्यटन में भी अच्छा काम कर रहा है. उज्जैन और ओंकारेश्वर के उदाहरण को लेते हुए अब अन्य धार्मिक स्थलों का विकास भी सरकार की प्राथमिकताओं में स्थान रख रहा है. इन धार्मिक स्थलों में कॉरिडोर निर्माण, रोप वे निर्माण, किलों का रख रखाव प्रमुख है. बजट में एक अच्छा प्रयास परम्परागत कलाओं, लोक गीतों बोलियों के संरक्षण पर भी है. मध्य प्रदेश में विभिन्न बोलियां बोली जाती है आधुनिकता की हवा में यह लुप्त होती जा रही थी, इन्हें संरक्षण की तीव्र आवश्यकता है.

वित्त वर्ष 2026-27 का यह बजट केंद्रीय बजट की परछाई है. हर वर्ग को साधने की कोशिश है. प्रधानमंत्री... शब्द से प्रारंभ हुई योजनाओं की पुनरावृत्ति वित्त मंत्री की प्रधानमंत्री जी के लिए प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है या विकसित भारत 2047 में मध्य प्रदेश के योगदान को प्रदर्शित करता है. बजट की आलोचना इस तथ्य में निहित है जो विपक्ष ने भी सदन में उठाई. कहीं यह बजट ऋणम कृत्वा... तो नहीं है. सरकार निरंतर कर्ज ले रही है और इतने अधिक कर्ज के बावजूद भी जो सौगात दे रही है उनके लिए वित्त की व्यवस्था कहां से होगी ? लाडली बहनों के लिए राशि बढ़ाने का प्रावधान है. किसानों के लिए अनेक प्रावधान है. उद्यमियों के लिए भी अनेक प्रावधान है. कर्मचारियों के लिए केवल शुक्रिया है. महंगाई भत्ते के लिए उन्हें और इंतजार करना होगा.

बजट

बजट भाषण के बीच विपक्ष का हंगामा

भोपाल. उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के बजट भाषण के दौरान विपक्ष ने पूरे समय टोका-टाकी की. सत्तारुढ़ दल के सदस्य जहां बजट में किए गए प्रावधानों को लेकर मेजें थपथपाकर लगातार स्वागत करते रहे, वहीं विपक्षी सदस्य बजट में किए जा रहे प्रावधानों को लेकर लगातार आपत्ति जताते रहे. इससे कई बार सदन में शोर-गुल की स्थिति भी बनी. विपक्षी सदस्य नल-जल योजना को प्रदेश की सबसे भ्रष्ट योजना करार देते रहे, इस बीच विपक्ष के ओमकार सिंह मरकाम एक हाथ में कटोरी जैसा कुछ सामान और एक कागज लेकर आसंदी के सामने जा पहुंचें, अध्यक्ष ने उनके इस आचरण को अनुचित करार दिया. बाद में मरकाम अपनी सीट पर वापस आ गए. विपक्ष ने विधायक निधि की राशि में बढ़ोतरी नहीं होने पर भी कड़ी आपत्ति जाहिर की. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मौजूदा राशि का अपर्याप्त करार दिया. उनका साथ विपक्ष के अन्य सदस्यों ने भी दिया. बजट भाषण के दौरान जैसे ही उप मुख्यमंत्री ने 74 हजार करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे का जिक्र किया तो नेता प्रतिपक्ष ने इस पर गहरी आपत्ति जताते हुए सवाल किया कि आखिर सरकार इस घाटे की भरपाई कैसे करेगी? इसका कोई रास्ता नहीं बताया गया है. इस बीच नेता प्रतिपक्ष की बातों के समर्थन में कई विपक्षी सदस्य सीटों पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे. इनमें से कई सदस्य आसंदी के सामने जा पहुंचे. विपक्ष की नारेबाजी का सिलसिला बजट भाषण के समाप्त होने तक चलते रहा.

बढ़ते कर्ज के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

विशेष संवाददाता

भोपाल. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने बजट सत्र के तीसरे दिन विधानसभा परिसर में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार मध्यप्रदेश को असहनीय कर्ज के बोझ तले दबा रही है. विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष एकत्रित हुए विधायकों ने हाथों में खाली गुल्लक और सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में नारे लिखी तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया. उनका आरोप था कि सरकार "आंकड़ों की बाजीगरी" के जरिए प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति को छिपा रही है. उमंग सिंघार ने दावा किया कि प्रदेश पर कुल कर्ज का बोझ 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है, जो राज्य के बजट से भी ज्यादा है. उन्होंने बजट सत्र से पहले 5,600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेने को भी गैर-जिम्मेदाराना कदम बताया. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि गुल्लक जनता की तिजोरी का प्रतीक है और करदाताओं के पैसे की बर्बादी हो रही है. उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण को "झूठ का पुलिंदा" बताते हुए प्रदेश की वास्तविक वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की.

पेज एक का शेष

ज्ञान से अब ज्ञानी पर फोकस

यशोदा योजना के तहत अब ट्रेटा पैक में बच्चों को दूध पिलाएगी सरकार : वैसे तो राज्य सरकार अपनी पूर्ववर्ती ज्यादातर योजनाओं को ही बरकरार रखेगी और उसके लिए राशि का प्रावधान बजट में किया है, लेकिन इस बजट में तीन बड़ी योजनाएं भी लांच की जा रही है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना यशोदा योजना है. 8 वीं तक पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को अब सरकार ट्रेटा पैक में दूध पिलाएगी. इस पर सरकार नये वित्तीय वर्ष में 700 करोड़ रुपए खर्च करेगी. इसका फायदा 80 लाख नौनिहालों को मिलेगा. पांच वर्ष में इस योजना पर सरकार 6600 करोड़ रुपए की बड़ी राशि खर्च करेगी.

शहरों की सूरत बदलेगी द्वारका नगर योजना : इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से लोगों की मौत की घटना के बाद अब सरकार प्रदेश के शहरों की सूरत बदलने के लिए द्वारका नगर योजना शुरू करेगी. इस योजना के माध्यम से शहरों के अधोसंरचना को मजबूत किया जाएगा. यानी शहरों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा. इस योजना में अगले तीन वर्षों में शहरों में बेहतर अधोसंरचना के लिए 5 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.

46 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति अब ग्रामीणों की : प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वालों को अब सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है. आबादी भूमि यानी निवासरत घरों की रजिस्ट्री नहीं होने से उनकी इस संपत्ति का बैंक या वित्तीय संस्थाओं के लिए कोई मोल नहीं था, लेकिन रजिस्ट्री हो जाने से ग्रामीण अब 46 हजार करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति के मालिक हो जाएंगे. इसके लिए राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 46 हजार करोड़ रुपए मूल्य की आबादी भूमि के स्वामित्य अधिकारों के पंजीयन के लिए 3800 करोड़ रुपए की बड़ी राशि का प्रावधान बजट में किया है. यानी रजिस्ट्री में खर्च होने वाली राशि सरकार देगी, मालिकाना अधिकार के लिए घरों के मालिकों को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा.

किसानों पर एक लाख 15 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे : राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है. लिहाजा किसानों के लिए खजाने की मुंह खोलने में कोई कमी नहीं की गई है. बजट में इस बार कृषि बजट के तहत एक लाख 15 हजार करोड़ रुपए की राशि का इंतजाम किया गया है. इसमें उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि पर 28158, मजबूत आदान व्यवस्था पर 64995, सुरक्षा चक्र पर 13769 और उपज का बेहतर मूल्य देने पर 8091 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.

गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर करने बड़ी राशि खर्च होगी : नए बजट में गरीबी को कम करने पर भी बड़ी राशि खर्च करने की तैयारी की गई है. राज्य सरकार का दावा है कि प्रदेश में गरीब जनसंख्या का अनुपात अब महज 20.63 फीसदी ही रह गया है. प्रदेश में एक करोड़ 36 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ चुके हैं. गरीबी उन्मूलन और समावेशी मानव विकास पर फोकस करते हुए सरकार ने बहुआयामी गरीब सूचकांक बजट भी पेश किया है, जिसके तहत पिछले बजट के मुकाबले 17 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. स्वास्थ्य में 24144, शिक्षा पर 31947 और जीवन स्तर पर 57288 करोड़ रुपए खर्च होंगे.